



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2007/7 वंशाख, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग
(स्टाम्प रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 17 अप्रैल, 2007

संख्या राजस्व 1-3 (स्टाम्प) 7/80-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते हैं कि जहां न्यायालय, वाद के पक्षकारों की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विवाद के परिनिर्धारण

के किसी एक ढंग को निर्दिष्ट करता है और जहां वादी को ऐसे न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र का हकदार बनाया गया है जो उसे ऐसे वादपत्र की बाबत संदत्त फीस की पूरी रकम को वापिस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो जिला कलेक्टर या उप-मण्डल कलेक्टर वादी को उसका प्रतिदाय करेगा।

आदेश द्वारा,

परमिन्दर हीरा माथुर,
अति० मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this notification No. Revenue 1-3(Stamp) 7/80-I, dated 17-4-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 17th April, 2007

No. Revenue 1-3 (Stamp) 7/80-I.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) read with section 16 of Court Fees Act, 1870, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that where the Court refers the parties to the suit to any mode of settlement of dispute referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 and where the plaintiff has been held entitled to a certificate by such Court authorizing him to receive back the full amount of the fee paid in respect of such plaint, the District Collector or the Sub-Divisional Collector shall refund the same to the plaintiff.

By order,

PARMINDER HIRA MATHUR,
ACS-cum-F. C. (Revenue).